प्रेस विज्ञप्ति

08 दिसंबर, 2017

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी; श्रीमति प्रियंका चतुर्वेदी, कन्वीनर, संचार विभाग, श्री पवन खेड़ा व श्री मनीष दोशी ने निम्नलिखित बयान जारी किया :–

भाजपा का 'संकल्प पत्र' है 'गुजरात विरोध पत्र'

भाजपा का कुशासन टिका चार सूत्रों पर– 'प्राईवेटाईजेशन', 'कमर्शियलाईजेशन', 'करप्शन' व 'एक्सप्लॉयटेशन'

भाजपा की सच्चाई है – न कोई विजन, ओनली टेलीविजन

22 साल के कुशासन के बाद हार का सामना करने कर रही भाजपा पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक अपना घोषणापत्र भी नहीं ला पाई। कल कांग्रेस उपाध्यक्ष, श्री राहुल गांधी के बयान के बाद आज आनन–फानन में 'भानमति का कुनबा जोड़' चुनाव से घंटों पहले एक गुजरात विरोधी 'कागज का पुलिंदा' पेश कर दिया गया। भाजपा भी जानती है कि इस 'दशाहीन व दिशाहीन' कागज के टुकड़ें को 6.5 करोड़ गुजराती पहले ही खारिज कर चुके हैं।

'गुजरात विरोधपत्र' ही भाजपा का एकमात्र उद्देश्य

दुर्भाग्य से श्री अरुण जेटली सहित सभी भाजपाई नेताओं ने गुजरात के विकास, सामाजिक सौहार्द्र व आर्थिक सबलता से जुड़े हर विषय का घोर विरोध किया। जैसे कि :–

1. **पाटीदार आरक्षण का विरोध।** श्री अरुण जेटली ने आज खुल्लमखुल्ला पाटीदारों से न्याय व आरक्षण की व्यवस्था का विरोध कर डाला। उस समय उनकी बगल में प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ साथ देश के कानून मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। कभी श्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र व वकील श्री हरीश साल्वे के माध्यम से और कभी देश के वित्तमंत्री व कानून मंत्री के माध्यम से भाजपा पाटीदारों के 'अनामत' का विरोध क्यों कर रही है?

2. **किसान की ऋणमाफी का विरोध।** श्री नरेंद्र मोदी व श्री अरुण जेटली पहले भी देश के किसान की ऋणमाफी के लिए भारत सरकार के खजाने से एक फूटी कौड़ी भी न देने का ऐलान कर चुके हैं। आज भाजपा ने कांग्रेस द्वारा गुजरात के किसानों को दी जाने वाली 24,000 करोड़ की ऋणमाफी का विरोध तक कर डाला। श्री जेटली यह बताना भी भूल गए कि 2008 में कांग्रेस की केंद्र सरकार की ₹ 72,000 करोड़ की ऋणमाफी का फायदा लेने से तत्कालीन भाजपा की सरकारों ने इंकार कर दिया था, जिनमें गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, बिहार व हिमाचल प्रदेश शामिल थे।

3. श्री अरुण जेटली व भाजपा द्वारा वित्तीय संकट का हवाला दे गुजरात की जनभलाई व फायदे की सारी योजनाओं का घोर विरोध किया गया।

किसानों के लिए कपास/मूंगफली/आलू/प्याज की फसलों पर सब्सिडी का विरोध। 4000 रु. प्रतिमाह के बेरोजगारी भत्ते का विरोध, युवाओं के लिए **32,000 करोड़ की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का विरोध, विद्यार्थियों की 80 प्रतिशत सीट्स कम करने के लिए सेल्फ फाईनेंस**

कोर्सेस को ग्रांट इन एड में बदलने का विरोध, प्रॉपर्टी टैक्स व बिजली के रेट कम करने का विरोध, हर महिला को मकान, युवतियों को मुफ्त शिक्षा का विरोध व आदिवासियों को सरकारी नौकरी व "जल–जंगल–जमीन' पर पट्टों के अधिकार का विरोध।

4. **पेट्रोल/डीज़ल की कीमतें कम करने का विरोध।** मई 2014 से आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने **पेट्रोल/डीज़ल पर** 11 बार एक्साईज़ ड्यूटी व दो बार कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है। पेट्रोल पर एक्साईज़ ड्यूटी मई, 2014 में 9.20 रु. प्रतिलीटर से बढ़ाकर 21.48 रु. कर दी गई, यानि 133.47 प्रतिशत का इजाफा। डीज़ल पर एक्साईज़ ड्यूटी 3.46 रु. प्रति लीटर से बढ़ाकर 17.33 रु. प्रतिलीटर कर दी गई, यानि 400.86 प्रतिशत का इजाफा। अकेले इसी से मोदी सरकार ₹2,67,000 करोड़ कमा रही है। इसीलिए कांग्रेस की मांग के बावजूद भाजपा पेट्रोल/डीज़ल को जीएसटी में नहीं ला रही।

5. **जीएसटी यानि गब्बर सिंह टैक्स के आर्किटेक्चर व डिज़ाईन को बदलने का विरोध।** आज भी कपड़ा उद्योग में धागे पर 12 प्रतिशत जीएसटी तथा कपड़े पर 5 प्रतिशत जीएसटी है। अकेले सूरत/राजकोट में इस कुप्रबंधन से 60,000 करोड़ सालाना का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार डायमंड उद्योग में अनपॉलिश्ड डायमंड पर 0.25 प्रतिशत जीएसटी, पॉलिश्ड डायमंड पर 2 प्रतिशत जीएसटी व लेबर पर 3 प्रतिशत जीएसटी है। इसने सूरत के डायमंड व्यापार को 30,000 करोड़ सालाना का नुकसान कर दिया है। वायदे के बावजूद 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हर व्यापारी को तिमाही जीएसटी 1 फॉर्म भरने की सुविधा भी झूठी निकली, क्योंकि जीएसटी नेटवर्क इसे आज भी मंजूर नहीं करता। जीएसटी फॉर्म 2 व 3 में दी गई सुविधा भी आज तक शुरु नहीं हो पाई। नतीजा यह है कि जुलाई से आज तक व्यापारी कोई फॉर्म फाईल कर ही नहीं पाए। परंतु भाजपा ने इन सबके बारे एक शब्द भी नहीं कहा।

6. **वार्षिक विकास दर के बारे भी भाजपा/वित्तमंत्री गुमराह कर गए।** नीति आयोग के मुताबिक 2015–16 में गुजरात की विकास दर गिरकर 6.7 प्रतिशत रह गई। 22 वर्ष पहले कांग्रेस शासन में यह विकास दर बहुत अधिक थी– 1981–85 (16.29 प्रतिशत), 1985–90 (13.63 प्रतिशत) व 1990–94 (16.73 प्रतिशत)।

कोरे वादे–झूठे इरादे

1. भारतीय जनता पार्टी की नीति, नीयत व रास्ते का सार तीन लाईनों में लिखा जा सकता है :–

न शासन, न प्रशासन

न रोजगार, न राशन

गुजरात को मिले, केवल जुमले और भाषण

2. भाजपा फसल की कीमत, सस्ती खाद व कृषि विकास की बात तो करती है, पर निर्णय इसके विपरीत है। खाद पर गुजरात सरकार ने 4 प्रतिशत वैट लगा रखा था, अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया गया है। कीटनाशक दवाईयों पर 18 प्रतिशत जीएसटी, ट्रैक्टर व खेती के उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। किसान की मूंगफली 4200 रु. प्रति क्विंटल की बजाए 800–1500 रु. प्रति क्विंटल में पिट रही है। यही हाल कपास का है, जो 3860 रु. प्रति क्विंटल के

एमएसपी के बजाए 2500 रु. प्रति क्विंटल में पिटती है। फसल बीमा योजना किसान फंसाई योजना बन गई है। 2016 में गुजरात में फसल बीमा राशि का प्रीमियम दिया गया– 2305 करोड़ रु.। परंतु किसानों को मुआवज़ा दिया गया, 125.69 करोड़ रु.। यानि कंपनियों को फायदा 1980.50 करोड़ रु. ।

3. भाजपा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की बात तो की गई, परंतु न तो नई जीआईडीसी खोली गई। उल्टा 55,000 लघु और मध्यम उद्योग बंद हो गए।

4. भाजपा कौशल विकास योजना की बात तो करती है, परंतु 15 लाख फिक्स्ड पे/ कॉन्ट्रैक्चुअल/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का 5500रु.–10,000 रु. देकर आर्थिक शोषण का कौशल दिखा रही है।

5. महिला सुरक्षा के बारे घोषणापत्र में एक शब्द नहीं कहा गया। यह भी इसके बावजूद कि भाजपा शासन में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में देश के 10 सबसे बड़े शहरों में अहमदाबाद व सूरत आते हैं। महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए अपराधों में केवल 3 प्रतिशत की सजा होती है तथा 97 प्रतिशत बरी हो जाते हैं। नलिया कांड के दर्द को आज तक भी गुजरात की महिलाएं नहीं भूल पाई।

6. भाजपा फीस नियंत्रण की बात तो करती है, परंतु फीस नियंत्रण कानून को लागू करने में फेल साबित होती है। सच्चाई यह है कि शिक्षा का व्यापारीकरण व महंगी शिक्षा ही सरकार का चेहरा बन गया है।

घोषणापत्र ने यह भी साबित कर दिया कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं। आश्चर्य तो यह है कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष तक का नाम व फोटो घोषणापत्र से गायब है। यह एक नेतृत्वविहीन हारी हुई पार्टी की दशा को दिखाता है।